



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 113 राँची, गुरुवार 7 फाल्गुन, 1936 (श०)  
26 फरवरी, 2015 (ई०)

#### परिवहन विभाग

-----  
॥ संकल्प ॥

17 फरवरी, 2015

विषय: झारखण्ड सरकार एवं रेलवे मंत्रालय भारत सरकार के बीच झारखण्ड राज्य अन्तर्गत निर्माणाधीन छः रेल परियोजना के निर्माण हेतु पूर्व एम.ओ.यू. (Memorandum of Understanding) - की वैधता फरवरी, 2013 में समाप्त होने के उपरान्त एम.ओ.यू. विस्तारीकरण (मार्च, 2017 तक) की स्वीकृति तथा परियोजनाओं की प्राक्कलित राशि में द्वितीय पुनरीक्षण के फलस्वरूप 5775.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति एवं एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना मांग संख्या-47-परिवहन विभाग, बजट मुख्य शीर्ष -3075-अन्य परिवहन सेवाएँ के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रेलवे को सहायता अनुदान मद में ₹ 66,18,00,000 (छियासठ करोड़ अठारह लाख रुपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-परि0वि0- -88/09/137-- झारखण्ड सरकार एवं रेल मंत्रालय भारत सरकार के बीच झारखण्ड राज्य में छः रेलवे परियोजनाओं के लिए सर्वप्रथम दिनांक 19 फरवरी, 2002 को निम्नानुसार

कुल 1997.00 करोड़ रुपये की लागत पर झारखण्ड राज्य एवं रेल मंत्रालय की क्रमशः 66.67% तथा 33.33% देनदारी के आधार पर एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया था ।

क्र0	परियोजनाओं का नाम	लम्बाई	प्राक्कलित राशि
1-	रांची-बरकाकाना-हजारीबाग-कोडरमा	189 KM	1002.00 CRORE
2-	रांची-लोहरदगा अमान परिवर्तन एवं टोरी तक विस्तार	113 KM	216.00 CRORE
3-	कोडरमा-तिलैया	14 KM	74.00 CRORE
4-	कोडरमा-गिरिडीह	105 KM	351.00 CRORE
5-	देवघर-दुमका	60 KM	200.00 CRORE
6-	दुमका-रामपुरहाट	64 KM	154.00 CRORE
		545 KM	1997.00 CRORE

2. परन्तु उक्त अवधि में रेलवे परियोजनाएँ पूर्ण नहीं की जा सकी । जिस कारण इस एम.ओ.यू. की अवधि दिनांक 18 फरवरी, 2007 को समाप्त होने के उपरान्त एम.ओ.यू. विस्तारीकरण हेतु एक प्रारूप तैयार किया गया तथा इस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर दिनांक 14 फरवरी, 2012 को केन्द्र सरकार के साथ एम.ओ.यू. पर मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया गया । इस एम.ओ.यू. विस्तारीकरण की अवधि फरवरी, 2013 तक थी । इस एम.ओ.यू. विस्तारीकरण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दिनांक 15 मार्च, 2012 की बैठक में की गई । विस्तारीकृत एम.ओ.यू. में विगत वर्षों में निर्माण सामग्रियों की मूल्य वृद्धि होने के फलस्वरूप इन रेल परियोजनाओं की मूल प्राक्कलित राशि को निम्नांकित रूप से संशोधित करते हुए 3771.00 करोड़ रुपये किया गया है ।

क्र०	परियोजनाओं का नाम	लम्बाई	प्राक्कलित राशि
1-	रांची-बरकाकाना-हजारीबाग-कोडरमा	200 KM	1800.00 CRORE
2-	रांची-लोहरदगा अमान परिवर्तन एवं टोरी तक विस्तार	113 KM	456.00 CRORE
3-	कोडरमा-तिलैया	14 KM	133.00 CRORE
4-	कोडरमा-गिरिडीह	105 KM	603.00 CRORE
5-	देवघर-दुमका	60 KM	358.00 CRORE
6-	दुमका-रामपुरहाट	64 KM	421.00 CRORE
		556 KM	3771.00 CRORE

3. एम.ओ.यू. विस्तारीकरण में झारखण्ड सरकार द्वारा रेल मंत्रालय, भारत सरकार से निर्माणाधीन इन छः परियोजनाओं के funding pattern को 66.67: 33.33 के स्थान पर 50: 50 किया गया। किन्तु लागत सहभागिता का संशोधित अनुपात इन परियोजनाओं की मूल प्राक्कलित राशि 1997.00 करोड़ रुपये पर लागू लागू नहीं था। 50: 50 का नया funding pattern इन परियोजनाओं के बढ़े हुए प्राक्कलित राशि अर्थात्  $3771.00 - 1997.00 = 1774.00$  करोड़ रुपये पर लागू हुआ। इस प्रकार 1774.00 करोड़ रुपये का 50 प्रतिशत अर्थात् 887.00 करोड़ रुपये की देयता राज्य सरकार की हुई। मूल प्राक्कलित राशि (1997.00 करोड़ रुपये) की 66.33 प्रतिशत की देनदारी के अनुरूप राज्य सरकार की देयता 1332.00 करोड़ रुपये तथा बढ़ी हुई राशि का 50%, 887 करोड़ रुपये अर्थात्  $(1332.00 + 887.00 = 2219.00)$  करोड़ रुपये के विरुद्ध रेल मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2012-13 तक राज्य सरकार की कुल देनदारी 2219.00 करोड़ रुपये निर्गत किया जा चुका है।

रेलवे के द्वारा उपलब्ध करायी गई विवरणीनुसार परियोजनावार मार्च, 2014 तक व्यय की स्थिति निम्नवत् है (राशि करोड़ में)

क्र०	परियोजनाओं का नाम	लम्बाई	प्राक्कलित राशि	मार्च, 14 तक रेलवे द्वारा व्यय की गई राशि	मार्च, 14 तक राज्य सरकार द्वारा रेलवे को उपलब्ध करायी गई राशि
1-	रांची-बरकाकाना-हजारीबाग-कोडरमा	203 KM	3211.00	763.00	1097.00
2-	रांची-लोहरदगा अमान परिवर्तन एवं टोरी तक विस्तार	113 KM	596.00	174.00	246.00
3-	कोडरमा-तिलैया	14 KM	150.00	27.67	52.33
4-	कोडरमा-गिरिडीह	111KM	927.00	246.50	363.50
5-	देवघर-दुमका	60 KM	400.00	166.67	233.33
6-	दुमका-रामपुरहाट	64 KM	491.00	189.33	240.67
		<b>565KM</b>	<b>5775.00</b>	<b>1567.17</b>	<b>2232.83</b>

- 4 परन्तु झारखण्ड राज्य में चलायी जा रही रेल परियोजनाएँ अबतक पूर्ण नहीं होने के कारण एम.ओ.यू. की अवधि समाप्त होने के उपरान्त, अवधि विस्तारित करने हेतु रेलवे मंत्रालय द्वारा नया एम.ओ.यू. प्रारूप समर्पित किया गया है तथा परियोजनाओं को मार्च, 2017 तक पूर्ण करने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रस्तावित एम.ओ.यू. विस्तारीकरण प्रारूप के अनुसार रेल परियोजनाओं की प्राक्कलित राशि निम्नरूपेण पुनरीक्षित की गई है:-

क्र०	परियोजनाओं का नाम	लम्बाई	प्राक्कलित राशि
1-	रांची-बरकाकाना-हजारीबाग-कोडरमा	203 KM	3211.00 CRORE
2-	रांची-लोहरदगा अमान परिवर्तन एवं टोरी तक विस्तार	113 KM	596.00 CRORE

3-	कोडरमा-तिलैया	14 KM	150.00 CRORE
4-	कोडरमा-गिरिडीह	111 KM	927.00 CRORE
5-	देवघर-दुमका	60 KM	400.00 CRORE
6-	दुमका-रामपुरहाट	64 KM	491.00 CRORE
		556 KM	5775.00 CRORE

निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 50: 50 का नया funding pattern इन परियोजनाओं के बड़े हुए प्राक्कलित राशि अर्थात्  $5775.00 - 1997.00 = 3778.00$  करोड़ रुपये पर लागू होगा। इस प्रकार 3778.00 करोड़ रुपये का 50 प्रतिशत अर्थात् 1889.00 करोड़ रुपये की देयता राज्य सरकार की होगी। इस प्रकार राज्य सरकार की देयता मूल प्राक्कलित राशि (1997.00 करोड़ रुपये) का 66.33 प्रतिशत 1332.00 करोड़ रुपये एवं वर्तमान पुनरीक्षित दर का 50 प्रतिशत 1889.00  $(1332.00 + 1889.00) = 3221.00$  करोड़ रुपये होगी राज्य सरकार द्वारा रेल मंत्रालय को अबतक 2219.00 करोड़ रुपये निर्गत किया जा चुका है, अतएव राज्य सरकार की कुल शेष देनदारी  $(3221.00 - 2219.00) = 1002.00$  करोड़ रुपये होगी। इस प्रकार एम.ओ.यू. विस्तारीकरण पर निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की देनदारी कुल 1002.00 करोड़ रुपये की होगी।

5. यह भी निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य में कार्यान्वित छः रेल परियोजनाएँ का एम.ओ.यू. विस्तारीकरण की अंतिम तिथि मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जाय। भू-अर्जन में होने वाले विलम्ब के लिए उपायुक्त पूर्ण रूप से जवाबदेय होंगे, इस कार्य की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव स्तर पर टास्क फोर्स का गठन होगा।
6. झारखण्ड राज्य में कार्यान्वित छः रेल परियोजनाएँ का एम.ओ.यू. मार्च, 2017 तक विस्तारीकरण एवं विस्तारीकरण के पश्चात् बढ़ोत्तरी की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में रेलवे को निर्गत की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं रेलवे द्वारा उक्त अवधि में निर्गत राशि का विवरण उपलब्ध उपलब्ध कराने के पश्चात् राशि विमुक्त की जाएगी।
7. एम.ओ.यू. विस्तारीकरण के फलस्वरूप बढ़ोत्तरी राशि में झारखण्ड सरकार को देयता की राशि 1002.00 करोड़ रुपये बजट शीर्ष -मांग संख्या-47-परिवहन विभाग, मुख्य शीर्ष -3075-अन्य परिवहन सेवाएँ-उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य-लघु शीर्ष-101-लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता-उप शीर्ष-01-झारखण्ड राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रेलवे का सहायता अनुदान

(केन्द्रांश-1: राज्यांश-2)-विस्तृत शीर्ष -06-अनुदान-78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान अन्तर्गत उपबंधित 26.18 करोड़ रुपये तथा लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष-01-झारखण्ड राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रेलवे को सहायता अनुदान (केन्द्रांश-1: राज्यांश-2)-2)-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-78 पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित 40.00 करोड़ रुपये अर्थात् वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित कुल राशि 66.18 करोड़ रुपये एवं अन्य शेष राशि अगामी वर्षों में उक्त शीर्ष में बजट उपबंध की राशि से विकलनीय होगा ।

8. रेलवे द्वारा योजना को पूरा करने के संदर्भ में उल्लेखित समस्याओं यथा-भू-अर्जन में विलम्ब, विधिव्यवस्था व्यवस्था का संधारण आदि से परिवहन विभाग सहमत है। तदनुसार मार्च, 2017 तक एम.ओ.यू. विस्तारीकरण के पश्चात् अगर रेलवे द्वारा उल्लेखित समस्याओं को राज्य सरकार द्वारा दुरुस्त करने पर योजना ससमय पूरा नहीं होने की स्थिति पर भविष्य में रेल परियोजना के लागत के बढ़ोत्तरी में राज्य सरकार की देनदारी नहीं होने का विकल्प खुला रहेगा ।
9. झारखण्ड सरकार एवं रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार के बीच झारखण्ड राज्य अन्तर्गत निर्माणाधीन छः रेल परियोजनाओं के निर्माण हेतु पूर्व एम.ओ.यू. (Memorandum of Understanding) की वैधता (मान्य अवधि फरवरी, 2013 तक) समाप्त होने के उपरान्त एम.ओ.यू. का विस्तारण मार्च 2017 तक के लिए अवधि विस्तार विस्तार की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को सम्पन्न बैठक में प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह./-(अस्पष्ट)

सरकार के सचिव

-----